जाती है इसलिए क्या ऐसी व्यवस्था भी आप करने जा रहे हैं कि गाड़ियों के अन्दर भी बीमार पड़ने वाले यात्रियों का डाक्टरों द्वारा का इलाज करने की व्यवस्था हो सके ?

Shri Parimal Ghosh: I could not exactly follow what the hon. Member meant. If specific things are given to me, I will definitely look into them.

श्री हुकम चन्द कछवाय : डाक्टरों की संख्या पूछी है . . . .

Shri Bal Raj Madhok: This was his specific question. In the railway trains, specially in the long-journey railway trains, some people get ill in the trains and he is asking whether you are going to make any proposal to have doctors going with the trains so that they can attend to the medical needs of the passengers.

Shri Parimal Ghosh: At the present moment, there is no such proposal. But if that kind of demand comes, we will certainly look into it.

श्री रामावतार शास्त्री : कोई भी डाक्टर एक रेलवे अस्पताल में कितने दिनों तक रह सकता है ? इस के लिए उन की कोई अवधि निश्चित है या नहीं, अगर है तो वह अवधि क्या है ? उन के लिए टाइम निश्चित होने के बाद भी किसी किसी अस्पताल में 6, 6 और 7, 7 साल तक वही डाक्टर बना रहता है तो इस का क्या कारण है ?

Shri Parimal Ghosh: The service conditions of the Railway Medical Officers and of the Health Services are exactly the same, as I have said before.

Closure of Textile Mills

*943. **Shri Beni Shanker Sharma:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri George Fernandes:
Shri Madhu Limaye:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the number of textile mills which were either not running or were closed down and were consequently taken over by Government during the last two years;

(b) whether those mills showed profits consequently;

(c) if so, the main features thereof; and

(d) whether those mills have since been handled over to their owners?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) to (d). A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

The management of Eight textile mills was taken over by the Central Government during 1965-66 and 1966-67.

Out of the eight mills taken over two are lying closed owing to financial difficulties. The State Government concerned are, however, taking steps to resume working. Of the remaining six, two started working only recently and their profit and loss accounts are not yet available. The audited balance sheets of the remaining four mills are not yet available. However, from the periodical reports received from the Authorised Controllers, it is observed that one of the four mills viz. The India Unted Mills has been making losses consistently though the amount of loss varied from month to month. The other three mills viz., Muir Mills Ltd., Kanpur Swadeshi Cotton and Flour Mills, Indore and Hira Mills Ltd., Ujjain, have making losses in some months and profits in some other months.

(d) No, Sir.

श्री बेणीशंकर शर्मा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बन्द मिलों की संख्या राज्यों के आधार पर (स्टेट वाइज,) कितनी है और उन मिलों में मोटा कपड़ा बनता था या फ़ाइन कपड़ा बनता था ?

श्री दिनेश सिंह : कुल 27 मिलें इस वक्त बन्द हैं । किन-किन प्रदेशों की कौन-कौन हैं यह विवरण मेरे पास है और अध्यक्ष महोदय, इसको मैं आपके पास भेज दूंगा ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मंत्री महोदय ने अपने इस बयान में जिन मिलों का जिक्र किया है उनमें बम्बई की दी इंडिया यूनाइटेड मिल्स का भी जिक्र है । मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि जब यह मिलें आज नुकसान में चल रही हैं तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने के लिए तैयार है कि इन मिलों में बना हुआ कपड़ा एक तो सरकारी काम में जहां जहां भी जरूरत पड़नी हो वहां पर, दूसरे पलटन के लिए और तीसरे विदेशों में अर्थात् ऐसे मुल्कों में उसका निर्यात करने के लिए जहां कि उस कपड़े की मांग है, ऐक्साइज ड्यूटी इत्यादि माफ़ करके यह कपड़ा भजने की व्यवस्था सरकार करेगी ? चूंकि मेरे पास वही प्रश्न है कि इस कपड़े को बाजार से हटाने की कोशिश वाजवी (निजी) क्षेत्र की मिलों की ओर से होती है और इसका सबूत आज बम्बई शहर में कई लोगों के पास है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने जो बात कही है आखिर में वह ज्यादा आवश्यक है कि कहा जाता है कि इस मिल के कपड़े के बिकने में लोग कुछ कठिनाई पैदा करते हैं । मुझे आशा थी और माननीय सदस्य मुझसे भी मिले थे और कल भी वह मुझसे मिलने वाले थे और मैं जानना चाहता था उन से इसके बारे में कि क्या वहां की स्थिति है और उसमें हम क्या कर सकते हैं ? उस में जो कोई बात हमें मालूम होगी हम उस की पूरे तरीके से जांच करेंगे । ऐक्साइज ड्यूटी हटाने का जहां तक सवाल है तो वह कोई हल नहीं है कि एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में डाल दिया और वही खाली सवाल नहीं है । यह मिलें खास कर जो इंडिया यूनाईटेड मिल्स के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि वह बड़े नुकसान पर चल रही है, कमेटी भी इसके बारे में बैठी, उसके भी सुझाव आये और उसके सुझाव काफ़ी उसकी जड़ पर जाते हैं । उन पर विचार हो रहा है । इस पर हमें कोई निर्णय करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस मिल को ठीक करें ? यह एक बहुत पेचीदा सवाल है ।

श्री बामानी : शोलापुर की स्पिनिंग मिल्स में जिसमें 10,000 व्यक्ति काम करते हैं आज चार वर्ष से बन्द पड़ी है और उससे शहर की जो आबादी है उस पर काफ़ी असर पड़ा है तो क्या उसको चलाने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात कई मर्तबा इस सदन में आई है दरअसल मिल को चला देना काफ़ी नहीं है बल्कि मिल चलती रहे इसकी तरफ़ देखना है आज सरकार के ऊपर क्या जिम्मेदारी है मिल को चलाने की यह भी एक बात देखने की, है । लोग मिलें शुरू करते हैं, किसी न किसी वजह से वह बन्द हो जाती हैं, कुछ इन्तजाम खराब हुआ, कुछ रुपये की गड़बड़ी हो गयी कुछ और वजह हुई । कोई बहुत पुरानी मिलें हैं जो आजकल ठीक से नहीं चल पातीं वह फिर बन्द होती हैं । मुझ कहते हैं सरकार इनको चलाये । सरकार इनको कैसे चलाये ? अगर अच्छे तरीके से चल सकती होतीं तो मिल मालिक उसको खुद ही चलाते । उसमें दिक्कत यह आती है कि जो मिल चल सकती है उन्हें सरकार चलावे । यह बात ठीक है जबकि इन्तजाम की वजह से खराबी हो या जिसमें लोगों ने पैसे की गड़बड़ कर दी हो

उसको सरकार चलाये यह बात तो ठीक है। खास सवाल तो यह है कि यह मिलें चलती रहें और इसमें जो मजदूर काम करते हैं उनको तकलीफ़ न हो। मैंने इस सदन में कहा है कि हम एक यहां पर विधेयक लाने वाले हैं जिसके अनुसार सरकार इन मिलों को चलायेगी लेकिन यही काफ़ी नहीं है क्योंकि इनको चलाकर फिर वापिस करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो मिल हमको लेना पड़े चलाने के लिए उसको हम हमेशा के लिए ले लें और वह एक पब्लिक सेक्टर की कारपोरेशन बना कर करें।

श्री सि० चं० झा : क्या यह बात सही नहीं है कि कोयम्बटूर की सूती मिलों की हालत के बारे में लोकनाथन कमेटी ने स्टडी की थी और उसने वहां पर कुछ सूती मिलें सिक पाई थीं तो जो मिलें सिक पाई गई थीं उनको सरकार लेने को तैयार है या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : अभी मैंने इसे काफ़ी विस्तारपूर्वक अर्ज किया है।

Shri Shivananjappa: Certain textile mills in Mysore State are proposed to be taken over. May I know the names of these mills?

Shri Dinesh Singh: When we take them over, the hon. Member will be informed.

Shri S. A. Dange: With particular reference to the Indian United Mills in Bombay City which employ about 20,000 workers, will tht hon. Minister tell us whether there were two inquiry reports about the functioning of the mills, whether in one report a fraud of Rs. 96 lakhs was discovered, whether Government tried to recover that money from the Directors and others who misappropriated that money and whether, if those efforts were not made, now efforts will be made to recover that money because of which the mills have gone into losses?

Shri Dinesh Singh: I can assure the hon. Member that now that he has brought this to my attention, I shall have it looked into and every effort will be made to recover this money.

श्री तुलशीदास जाधव : अभी मंत्री महोदय ने साल भर पुरानी मिल के लिये उत्तर दिया। आज वहां कम से कम 2 या 2॥ करोड़ की जायदाद है जो कि हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। सरकार उसे लेने के लिये तैयार है, वर्कर्स तैयार हैं, पैसा भी सरकार के पास है। अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वह और स्टेट गवर्नमेंट मिल कर उस को चलाये। 6 हजार वर्कर्स को उस से पैसा मिलता है। तीन साल हो चुके हैं सरकार उसके बारे में विचार क्यों नहीं करती है ?

श्री दिनेश सिंह : बिना इस मामले में विस्तार में गये हुए मैं माननीय सदस्य से इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां वह तीन साल तक रुके, वहां तीन महीने और रुक जायें और हमारे कारपोरेशन को बनने दें।

Shri Piloo Mody: The hon. Minister said that he was going to take over the textile mills and he was not satisfied with doing it on a temporary basis but he wanted to do it on a permanent basis because the mills were not being run properly. Would the hon. Minister also consider handing over to the private sector the umpteen public sector undertakings which are not being run properly?

Shri Dinesh Singh: No, there is no such question.

Shri Piloo Mody: Is he going to consider it?

Shri M. R. Krishna: One of the mills in Sholapur, namely the Narsingghirji mills was taken over by Government and its management was entrusted to a special committee. My information is that the new management is also incurring great loss

What is the present position of that mill?

Shri Dinesh Singh: I did not catch the name of the mill.

Shri M. R. Krishna: It is the Narsingghirji mills.

श्री एस० एम० जोशी : क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि इंडिया यूनाइटेड मिल्स में आज कल कितने रुपये माहवार का ह्रास होता है ?

श्री दिनेश सिंह : माहवार के आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं है।

Shri S. Kandappan: May I know whether it is a fact that the rise in the cost of production of cotton fabrics is having an adverse effect on the consumption of cloth in the internal market and if so, what the Government propose to do to arrest the increase in the cost of production?

Shri Dinesh Singh: It is a much wider question which goes into the question of the internal wage and cost structure.

Shri S. Kandappan: But that is the basic *question*.

Shri Dinesh Singh: I do not know whether I can explain it in a brief reply during the Question Hour.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether the attention of Government has been drawn to the fact that in Andhra Pradesh where some textile mills have been started with a spindlage of 12,000, they are not working on an economic basis and they have represented to Government that if a third shift were allowed, they would be able to work the mills on an economic basis and if not, the mills would be on the verge of closure, and if so, may I know whether Government will take suitable steps to allow such of those economic mills to work on an economic basis by allowing them to work a third shift?

Shri Dinesh Singh: We have no objection to the mills working as many shifts as they like. But the difficulty is that there is cotton shortage. We do not have enough cotton to allow the mills to work on three shifts. Owing to that reason, we have also placed certain restrictions on the adding of new spindlage etc. As soon as the cotton position improves we shall be very glad to allow them to work more shifts.

Shri P. Venkatasubbaiah: They are not asking for supply of cotton.

Shri Dinesh Singh: They iannot get it.

Shri S. M. Banerjee: I am happy at the statement of the hon. Minister that he has decided to take over some of these mills permanently. I would like to know whether his mind is working on the lines of having a textile corporation by bringing forward legislation here and if so, whether that legislation is likely to be brought forward before this House during this session?

Shri Dinesh Singh: Yes.

Shri Samar Guha: Will the hon. Minister let us know why the Dhakes wari Cotton Mills at Asansol has been closed....

Mr. Speaker: We cannot go into the cases of individual mills now.

Shri Samar Guha: There is some special reason. That is why I am mentioning it.

Govesnment give some sobaidy to it on the understanding that that particular mill will employ refugees from East Pakistan. That mill is lying closed. May I know whether Government are prepared to undertake the running of this mill particularly for the reason that the refugees may be employed there.

Shri Dinesh Singh: I shall have it looked into.

Shrimati Lakshmikanthamma: Is it a fait that the high price of cloth and the low purchasing power in the hands of the people are responsible for the stagnation in the textile industry, and if so, may I know whether Government will think of controlled distribution of cloth to the people at controlled prices?

Shri Dinesh Singh: The price of cloth of mass consumption is already controlled, and we are not aware of any great difficulties being experienced in that connection.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस टैक्सटाइल मिल को भोपाल रिलीफ ऐक्ट के अन्तर्गत शासन ने फरवरी 1966 में लिया अपने हाथ में उसको अगस्त 1966 के अन्दर ही अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अपने हाथ में लेने के बाद शासन ने उसको बन्द क्यों कर दिया। आज 2,000 मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। उन्हें जो प्राविडेंट फन्ड मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है।

श्री दिनेश सिंह : यह बात सही है कि भोपाल में न्यू टैक्सटाइल मिल को लिया गया था और उसको शुरू भी किया गया था, लेकिन शुरू करने के बाद भी वह चल नहीं सकी और उसे फिर बन्द किया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसको देख रही है और उसको शीघ्र से शीघ्र फिर चलाने की कोशिश की जायेगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वहां के मुख्य मंत्री को इस मिल मालिक ने फ्री बंगला रहने के लिये दे रखा है। सरकार इसके बारे में क्या करेगी? इसके बन्द करवाने में मुख्य मंत्री का प्रमुख हाथ है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य मझसे बेकार नाखुश हैं, मैं ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही।

श्री हुकम चन्द कछवाय : केन्द्रीय सरकार इसमें क्या करेगी। जब वहां के मुख्य मंत्री को रिश्वत में रहने के लिये बंगला दे रखा है तब केन्द्रीय सरकार कर भी क्या सकती है?

श्री कंवर लाल गुप्त : सवाल यह है कि प्राविडेंट फन्ड नहीं दिया गया। इस के बारे में क्या जवाब है?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ आक्षेप मुख्य मंत्री पर लगाये हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना मुनासिब है क्योंकि मुख्य मंत्री यहां पर जवाब देने के लिये नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप खोज कीजिये इस के बारे में तब आपको सब कुछ मालूम हो जायेगा।

श्री दिनेश सिंह : इस प्रकार के आरोप यहां नहीं लगाये जाने चाहिये।

Mr. Speaker: I will not allow this. If he repeats it, it will not be good. He has understood the question.

Shri Kanwarlal Gupta: He must answer the question.

Mr. Speaker: Let him reply and if there is anything further to clarify, he can ask.

Shri Kanwarlal Gupta: We have been requesting you to ask him to answer the question. He is not doing it.

सवाल यह किया गया था कि 2,000 मजदूरों को जो प्राविडेंट फंड दिया जाना चाहिये था वह क्यों नहीं दिया गया। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री दिनेश सिंह : यह तो मैं पता लगा कर बताऊंगा।

Shri Narendra Singh Mahida: The Raj Ratna Mills, Petlad, which is in my constituency, has been closed for the last 1½ years. A committee was appointed under the chairmanship of Shri Oza who was a member of this House, and its report has been submitted to Government. What reply has the Government of India given to the Gujarat Government in this connection?

Shri Dinesh Singh: The difficulty in all these questions is that hon. Members wish to go into cases of individual mills. If they would let me know that they wish to go into the cases of individual mills, I will very gladly give the facts. But it is difficult for me to recollect all the reports that have been submitted or other facts about individual mills.

Shri P. Ramamurti: Pondicherry is directly under the Central Government. In connection with the affairs of the Bharati Textile Mills, Pondicherry, a committee of M.Ps. was appointed and that committee had recommended ten months ago that the mill has to be taken over by the Central Government. What do Government propose to do with regard to the recommendation of that parliamentary committee?

Shri Dinesh Singh: I am sorry the hon. Member did not know the full facts. The mill was taken over in June 1966 and it is functioning from February 1967.

श्री डा० ना० तिवारी: अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कारपोरेशन बनने के बाद ऐसी मिलों को परमानेन्टली ले लिया जायेगा जिन में घाटा होता है या जिसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी मिलों के लेने के बाद सरकार उन को कम्पन्सेशन देने की बात भी सोचती है ? क्योंकि मिल को ले कर ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि मिलों को घाटा न हो और और उन का प्रबन्ध अच्छा हो जाये ।

श्री दिनेश सिंह : मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि । जितनी मिलें हैं वे सब हम ले लेंगे यह मैंने नहीं कहा है । जिन को मुनासिब समझेंगे उनको हम लेंगे । जो मुआवजा देना होगा या जो लिक्विडेशन प्राइस होगी या और जो तरीका होगा उसको यहां पर माननीय सदस्य तय करेंगे, उसके हिसाब से काम होगा ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने बताया है कि टैक्सटाइल का कारपोरेशन के गठन के लिये एक विधेयक वह प्रस्तुत करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल कारपोरेशन की रचना करते समय क्या मंत्री महोदय इस बात का ख्याल रखगे कि शासकीय खर्चा ज्यादा होने से वह एक दूसरा सफेद हाथी न बनें । दूसरी बात यह है कि जो माल पैदा होगा उसका वितरण और बिक्री का जब तक इंतजाम नहीं होगा टैक्सटाइल कारपोरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका भी कोई इंतजाम इस विधेयक के द्वारा आप करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : वितरण का तो अभी कोई विचार नहीं किया गया है और न कोई इसकी आवश्यकता हम समझते हैं । लेकिन पहला सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उस पर हम जरूर ध्यान देंगे ।

Price of Woollen Yarn

***244. Shri Abdul Ghani Dar:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the woollen yarn is being sold in the Indian market at a rate double than the control price;

(b) if so, the action being taken against those persons or firms who evade surcharge, income tax, sales-tax by selling the yarn in black-market; and